2025:AHC-LKO:63835

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW

APPLICATION U/S 482 No. - 2694 of 2007

Prabhu Chawla ....Applicant(s)

Versus

State of U.P. and another. ....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Akhilesh Kalra, Imran Ullah, Kumar Ayush, Nadeem Murtaza
Counsel for Respondent(s)	:	Govt. Advocate, Akhlaq Ali, Nishant Srivastava, Sanjay Srivastava, Shachindra Dwivedi, Syed Akil Ahmad, Vivek Kumar Singh

Connected with

APPLICATION U/S 482 No. - 2693 of 2007

Aroon Poorie ...Applicant(s)

Versus

State of U.P. and another ....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Akhilesh Kalra, Imran Ullah, Kumar Ayush, Nadeem Murtaza
Counsel for Respondent(s)	:	Govt. Advocate, Akhlaq Ali, Nishant Srivastava, Sanjay Srivastava, Shachindra Dwivedi, Syed Akil Ahmad, Vivek Kumar Singh

Court No. - 16

HON'BLE BRIJ RAJ SINGH, J.

1. Heard Shri Nadeem Murtaza, learned counsel for the applicants, learned A.G.A. for the State and perused the record.

2. However, no one has appeared on behalf of opposite party no.2.

3. The present 482 Cr.P.C. application along with connected 482 Cr.P.C. No.2693 of 2007 have been filed with a prayer to quash the summoning order dated 07.05.2007 whereby the applicants have been summoned under Sections 153/153A IPC as well as the entire criminal proceedings pending in the court of Special Judicial Magistrate, (CBI), Lucknow vide RBT No.C-186 of 2006 bearing Complaint Case No.626 of 2004, (Ehtisham Mirza vs. Arun Purie and others), Police Station Chowk, District Lucknow.

4. Since both the above petitions involve common questions of fact and law therefore, the same are being decided together.

5. It has been submitted that the applicant in Application No.2694 of 2007 is an Editor of Magazine, "India Today” whereas the applicant in Application No.2693 of 2007 is Editor-in-Chief of Magazine “India Today.”

6. The complaint was filed by the opposite party no.2 before the Special Judicial, Magistrate CBI, Lucknow against the applicants and others under Sections 500/153/153A IPC. The Magistrate after recording the statements under Sections 200 and 202 Cr.P.C. of the complainant and witnesses issued summons by taking cognizance vide impugned order and directed the applicants to appear before the court.

7. It has been submitted that on 13.10.2023, Hindi and English Edition of the Weekly Magazine of 'India Today' published an article titled "Girls for Sale and "Ladkiyo Ki Mandi"

respectively wherein magazines highlighted the burning issue of child labour and child prostitution racketing in different parts of the country. It was also highlighted in the article that how poor people in economically backward areas of the country are being duped to send their young girls for marriage or employment purposes to foreign countries. The whole intent and purpose of the article was to bring to the notice of the public at large and authorities.

8. It has been submitted that a bare perusal of the impugned article and summons show that no offence under Sections 153/153A IPC is made out and the Magistrate has erred in law while issuing summons to the applicants. It has been submitted that it is settled legal proposition that the court has to read complaint as a whole and find out whether allegations made in the complaint constitute an offence punishable under Sections 153/153-A IPC. He has further submitted that merely inciting the feelings of one community or group cannot attract either of the Section 153/153A IPC. But in the present case, the subordinate Court has not applied its mind properly and issued summons in a mechanical manner without looking into the fact that there is no ingredient available on record which may indicate that the Magazine had incited the two communities or groups to come to clash together.

9. Learned counsel for the applicants has further invited attention of this Court towards the Page No.26 of the application, contained as Annexure No.2 and has submitted that the source of information has been mentioned pertaining to Dr. Sunita Krishnan, Secretary, (Prajjawala') Manav Taskari Virodhi Sangathan, which is an Organisation based at Hyderabad wherein

she has mentioned that the poor parents are duped and their minor daughters are being sold to fulfill sexual desires of the Haj Pilgrims and the girls are used as sex slaves which creates unrest in Bediya Community. It has also been submitted that unrest prevailing in Bediya community does not mean that there is an incitement or clash between the two communities. The relevant portion of the article published in Magazine 'India Today' (Annexure 2) is quoted hereinbelow :

*"**लड़कियों की मंडी** मुंबई लड़कियों के अवैध व्यापार के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरी है, लड़कियों की खरीद - फरोख्त के संगठित धंधे के इस केंद्र में विभिन्न राज्यों की लड़कियां खरीदी बेची जाती हैं. यहीं से उन्हें पश्चिम एशिया के देशों और फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों को भेजा जाता है, इस काले धंधे के खिलाफ छापों में हर साल सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कियां यहीं से बरामद होती है।*

*उस लड़की के चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव दिखाई देता है-आतंक, पंजाब के चकलीशर गांव की एक तंग कुटिया में दागदार फर्श पर बैठी 14 वर्षीया दीपा लगातार सुबक रही है, बेतरतीब बिखरे बाल और गंदे नाखून उसकी दयनीय दशा दशति हैं, वह बांग्ला में कहती है, "मैं घर जाना चाहती हूं, वह मुझे मारेगा।" फर्श पर, गंदे बदबूदार कपड़ों के ढेर से लदी अलगनी के नीचे दो और लड़कियां एक दूसरे से सटकर बैठी हैं, एक देवी की फटी तस्वीर को निहार रही है और दूसरी अपने पतले कंधे को बार-बार दुपट्टे से ढकने का प्रयास कर रही है, ऊपर लटके बल्ब की मद्धिम रोशनी में तीनों एक-दूसरे की प्रतिरूप लगती हैं, **मुर्शिदाबाद** में एक ट्रक चालक ने हरेक लड़की के माता-पिता को 3,000 रु. दिए और उन्हें पंजाब ले आया, रास्ते में सड़क के किनारे एक शौचालय में दीपा के साथ बलात्कार भी किया गया।*

घर के आंगन में बूढ़ी महिला, जिसकी चमड़ी पर झुर्रियां पड़ गई हैं और कमर मुड़ गई है, चारपाई पर बैठी है। वह कहती है, "बचा लो उनको।" तभी एक मुच्छड़ व्यक्ति आ जाता है और उसे डांटता है, "तुम इससे दूर ही रहो, बेबे (मां)।" और फिर हमसे कहता है "बाहर निकल जाओ, कौन हो तुम लोग ?" मिट्टी की दीवारों के बाहर पांच पुरुषों और एक महिला से हमारा सामना होता है। वे लड़कियों को देखने पहुंचे हैं। जल्दी ही सौदेबाजी शुरू हो जाएगी।

धोखेबाजी, सौदेबाजी, मारपीट, गाली-गलौज, बलात्कार और जिस्मफरोशी मानव तस्करी लड़कियों के व्यापार की संवैधानिक व्याख्या भर है। जो दक्षिण एशिया में एक अरब डॉलर का कारोबार बन गया है संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) इसे आतंकवाद और मादक पदार्थों के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक कमाऊ अपराध मानते हैं। भारत दुनिया के मानव तस्करी के नक्शे में न केवल सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा है, बल्कि एशिया में ऐसे देश के रूप में उभरा है जहां

अपने ही देश के भीतर लड़कियों को सबसे अधिक खरीद-फरोख्त होती है।
औरतें सदियों से बिकती रही हैं, पर अब कमसिन लड़कियों की मांग बेहद बढ़ी है। गरीब माता-पिता उनसे कम उम्र में ही निजात पाना चाहते हैं लड़कियां इतनी मासूम होती हैं कि झूठे वादों से बहलाना-फुसलाना आसान होता है। यही नहीं, इन मिथकों ने कि कुंआरी लड़कियों पुरुषों को गुप्त रोगों से मुक्ति दिलाती है और यह कि कमसिन लड़कियां एचआइवी विषाणु की वाहक नहीं हो सकती, सेक्स बाजार में उनकी बिक्री को कई गुना बढ़ा दिया है।

दिल्ली शालू 13 साल की उम्र में दिल्ली के जीबी रोड पर आई थी क्योंकि आठ बहन-भाइयों, लकवाग्रस्त बाप और लाचार मां को पालने का यही जरिया था। अब उस पर आश्रितो की संख्या बढ़ गई है। 15 साल की उम्र में उसका पहला बच्चा हुआ, फिर गर्भवती है।

बेचते हैं

वेश्यावृत्ति के लिए
हर साल लाखों लड़कियां मोटी कीमत के एवज में दलालो, बाइयों के हाथों बेची जाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दी जाती है।

मजदूरी के लिए
कई एजेंसियां लड़कियों को खरीदकर उन्हें 100 रु. माह की मामूली रकम पर घरेलू काम के लिए या छोटे उद्योगों को देती है।

अवैध शादी के लिए
पंजाब में ज्यादातर ऐसे किसान खरीदते हैं जो शादी की हैसियत नहीं रखते, कई अनिवासी भारतीय भी इसके लिए खरीदते हैं।

भिक्षावृत्ति के लिए
गरीब घरों की लड़कियां खरीदकर और कभी अपहरण करके उनसे भारत या मध्य-पूर्व में हज के दौरान भिक्षावृत्ति करवाई जाती है।

नशे के धंधे के लिए
राजमार्गो, रेलवे स्टेशनों, अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नशीली दवाएं बेचने के लिए मासूम लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है ।

कमसिन जिस्मों का कारोबार

नाटी, सांवली और प्रिंटेड सलवार कमीज पहने मंजीत कौर, साधारण महिला दिखती है, पंजाब के छोटे-से गांव मंघानिया को यह महिला बंगाली लहजे में हिंदी, पंजाबी बोलती है। सिर से पांव तक मुझे घूरते हुए बोली, "मैं निपट अनपढ़ है, पर दुनियादारी की समझ है मुझमें" मानसा जिले में लड़कियों की कुख्यात मंडी चलाने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की, पर यह बेफिक है ।

चंडीगढ़ की एक ब्यूटी पॉर्लर को मालिक के रूप में परिचय देते हुए मैंने उससे कहा कि मैं लड़कियां खरीदकर उन्हें मसाज करने का प्रशिक्षण देना चाहती हूं। उसने तुरंत खाट बिछाई और स्टील के गिलास में पानी दिया, मुस्कुराते हुए पूछा "कैसी लड़कियां चाहिए? स्थानीय चलेंगी या बंगाली ही?" उसका कहना है कि उसके घर पुलिस का छापा उसे बदनाम करने

और उसके छोटे से खेत पर कब्जा करने के लिए उसके स्थानीय दुश्मनों की करतूत थी।

मंजीत किसी ठेठ पंजाबी महिला की तरह नहीं दिखती है और है भी नहीं। वह बंगाल के एक छोटे-से गांव की है और 18 साल पूर्व उसे खुद एक पंजाबी किसान के हाथ बेच दिया गया था, जिसने नाम के साथ-साथ उसकी अंतरात्मा भी बदल दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों से फुसलाकर लाई गई लड़कियों को पंजाब के ऐसे किसानों को बेचकर चांदी काट सकती है, जो शादी नहीं कर सकते या जो कई कारणों से वैध शादी नहीं करना चाहते। दशकों पहले शुरू हुआ मंजीत का यह कारोबार पिछले साल भर में एक मंडी बन गया है पति की मौत के बाद मंजीत नियमित तौर पर पश्चिम बंगाल से लड़कियां लाकर उन्हें यहां बेच देती। मानसा जिले में हर तरफ ऐसी खरीदी और बेची गई लड़कियां पाई जा सकती हैं।

पर्याप्त संख्या में खरीदार हो जाते तो मंजीत 8-10 लड़कियां ले आकर उन्हें तय जगह पर प्रदर्शित करती, ऊंचे कद की, गोरी लड़कियां 15,000 रु. से ऊपर में बिकती तो खूबसूरत लड़कियों का दाम 25,000 रु. तक मिलता। नाटी, सावली लड़कियां 10,000 रु. और उससे कम में जबकि मोटी और ज्यादा उम्र की लड़कियां कम दाम में बिकती हैं, उम्र जितनी कम हो, दाम उतना ज्यादा मिलता।

मंजीत नहीं मानती कि वह लड़कियों की खरीद-फरोख्त करती है। अपनी समाज सेवा को वह यह कहकर जायज ठहराती है कि गरीब मां-बाप खुद अपनी लड़कियां उसे सौंपते हैं तो वह उन्हें ठिकाने क्यों न लगाए, इस वर्ष अप्रैल में मंजीत कौर की मंडी में एक अनूठा ग्राहक आया। स्थानीय अखबार जागरण के संवाददाता बलदेव शर्मा ने एक नकली ग्राहक को साथ लिया और उसका भाई बनकर मंजीत के घर जा पहुंचे। उन्होंने एक लड़की से शादी करने के नाम पर उसे 22,000 रु. में खरीदा और घर जाने की बजाए पुलिस थाने पहुंचे। अगले दिन खबर छपी तो मानसा पुलिस ने मंजीत के घर छापा मारा। वहां से पता चला कि मंजीत दरसल पश्चिम बंगाल के बाइहिमीर गांव के निवासी राजू दलाल की सहयोगी है, जो अभी फरार है।

वैसे, मानसा के उपायुक्त राजकमल चौधरी कहते हैं, "मेरा मानना है कि ऐसी शादियां नहीं हुई।" मगर बुढलाडा के डीएसपी सुखपाल सिंह बरार ने स्वीकार किया कि मंजीत के घर पर छापा मारा गया था और उन्हें प्रमुख अभियुक्त राजू दलाल की तलाश है। फिर भी, पता नहीं मंजीत अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं की गई।

और वह अभी भी मुस्कुरा रही है। नये सौदे को उम्मीद में उसकी आंखों में चमक है। वह भरोसा देती है, "लड़कियां मिलते ही मैं फोन करूंगी." और खुशी-खुशी मेरा फोन नंबर लेकर कहती है, "जल्दी लौटना"

देश भर में किए गए नए अध्ययनों के मुताबिक, यह बीमारी कम उम्र की लड़कियों को अपना शिकार बना रही है। उनमें से कई लड़कियां एचआईवी पॉजिटिव हैं, और कई तो एड्स से पीड़ित हैं। हैदराबाद में जुड़े शेखों से होने वाली शादियां जारी है, लेकिन अब शेख नजर नहीं आते हैदराबाद स्थित मानव तस्करी विरोधी संगठन प्रज्वला की महसचिव डॉ

सुनीता कृष्णन का कहना है कि, "वे पोशीदा मानव तस्कर हैं जो गरीब माता-पिता को यह कहकर ठगते हैं कि उनकी बेटियां पश्चिम एशिया में हैं जबकि हकीकत यह है कि उन्हें जिस्मफरोशी के काम में लगा दिया जाता" पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, जो मानव तस्करी का पर्याय बन गया है, अब हज यात्रियों की वासना शांत करने के लिए कमसिन लड़कियों का सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरी ओर अपनी बेटियां वेश्यालयों को बेचने के लिए कुख्यात बेड़िया समुदाय उन्हें विदेश के बड़े ग्राहकों को बेच रहा है।

आंकड़े चौंकाने वाले हैं (देखें बॉक्स) लेकिन अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि आकड़ों से पैदा होने वाली सनसनी की बजाए सही आंकड़ा पाने के लिए आप्रवासन, वेश्यावृत्ति और महिलाओं तथा लड़कियों की तस्करी के आकड़ों को अलग करना चाहिए। लेकिन इस विषय पर काम कर रहे संगठन इस तथ्य से इनकार नहीं करते कि लड़कियों की तस्करी के मामलों में इजाफा हो रहा है और 9-15 वर्ष की आयु वाली लड़कियों की सर्वाधिक बिक्री हो रही है।

जब अलग-अलग लड़कियां और महिलाएं अपनी दास्तान सुनाती हैं तो इस अपराध के दिल दहलाने वाले पहलू उभरने लगते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोनौली सीमा के पार नेपाल के बेहेलिया की आठ वर्षीया उमा को एक सर्कस से आजाद कराया गया। कुपोषण की जर्द पड़ चुकी उस मासूम का कहना है कि "पैसा फेको, तमाशा देखो" वाक्य उसे सोने नहीं देता। वह अपनी मां की फटी-पुरानी साड़ी का किनारा पकड़कर शून्य में निहारने लगती है। उसे दूसरी लड़कियों के साथ सर्कस से छुड़ाकर घर पहुंचाने वाले 'एकता केंद्र' की नेपाली सामाजिक कार्यकर्ता तृष्णा शर्मा का कहना है, "माता-पिता इस बात से अनभिज्ञ थे कि खतरनाक कलाबाजियों के अलावा उनकी बेटियों का यौन शोषण भी किया जाता था और उन्हें एक शो के लिए मात्र 5 रु. दिए जाते थे।"

कोलकाता के सोनागाछी व मुंबई के कमाठीपुरा के वेश्यालयों की ज्यादातर लड़कियां नेपाली-बांग्लादेशी हैं। भारत - नेपाल सीमा पर काम करने वाले 'सेवा बियॉन्ड बॉर्डर' के कार्यकारी निदेशक जटाशंकर का कहना है, "सीमा के सभी रास्तों पर पुलिस का पहरा नहीं है सो, लड़कियों को पार कराना आसान है" उतर प्रदेश के महाराजगंज में ही प्रवेश के छोटे-बड़े 104 केंद्र हैं। ये लड़कियां अपने घरों में इतना वंचित जीवन जीती है कि लड़के उन्हें नौकरी दिलाने और उनसे विवाह का वादा करके उनके साथ सहवास करते हैं और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते हैं।

जिस्मफरोशी का धंधा कभी छोटे-मोटे दलालों या गांव की 'दाइयों' का क्षेत्र हुआ करता था लेकिन इस कारोबार से इतना पैसा जुड़ा हुआ है कि संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह इसमें शामिल हो गए, कोलकाता में 10 साल से कम उम्र की लड़कियों को वेश्यालयों के इर्दगिर्द के मयखानों और रेस्तरांओं में काम कराकर जिस्मफरोशी के लिए तैयार किया जाता है।

एनएचआरसी के एक्शन रिसर्च ऑन ट्रैफिकिंग इन विमेन ऐंड चिल्ड्रेन के दिल्ली स्थित शीर्ष अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक पी.एम. नायर सहमति जताते है, "अंतरराष्ट्रीय गिरोहों वाले संगठित अपराध के रूप में मानव तस्करी नई बात है" शीघ्र ही जारी होने वाले इस अनुसंधान के तहत देश मैं 11 राज्यों में शोध किया गया है। इसे यूनीफेम ने प्रायोजित किया है। ये

देश में मानव तस्करी पर अब तक के सबसे विश्वसनीय आंकड़े हो सकते हैं।

"मुझे डर लगता है, अब तो में मरना चाहती हूं"
पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया से अपने 'यार' द्वारा शादी का झांसा देकर लाई गई 14 वर्षीया प्रेमशीला पासवान से शेफाली वासुदेव की बातचीत.
कौन लड़का तुम्हें गोरखपुर लाया ?
उसे दो-तीन साल से जानती हूं. नाम नहीं, यही मालूम है कि वह कसाई है और मैं उसे प्यार करती हूं। बोला कि मुझे अपने चाचा के घर ले जाकर शादी कर लेगा।
उस लड़के सलीम खान ने पुलिस को बताया कि तुम उसका पीछा कर रही थी और वेश्यावृत्ति करती हो।
झूठ बोलता है, पिछले दो साल से, जब मेरी उम्र 12 साल थी, वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा है। दूसरे मर्दों को भी मेरे पास भेजता रहा है, कल से, जब हमने गांव छोड़ा, उसने अपने दोस्त की झोपड़ी में मेरे साथ 10 से ज्यादा बार बलात्कार किया है।
क्या तुम डरी हुई हो ?
हां, मैं मरना चाहती हूं.
तुम अपने मां-बाप के पास क्यों नहीं लौट जाती ?
मां-बाप मुझे नहीं चाहते. मैं 'गंदी' हो गई हूं और वे मुझे कभी वापस नहीं लेंगे।
मगर वह लड़का तुम्हें किसी दलाल के पास या कोठे में बेच देगा तो ?
इस बारे में सोचूंगी।
इस बाजार में किसी तरह का कोई संकोच या हिचक नहीं है। तस्कर मानसिक रूप से विक्षिप्त और दृष्टिहीन लड़कियों का भी कारोबार करते हैं, वे उनकी देखभाल करने के बहाने पहले उनसे दोस्ती गांठते हैं और फिर घिनौने पेशे में बेच देते हैं। संगठित गिरोह गांवों से लड़कियां खरीदने के लिए स्थानीय छोटे-मोटे अपराधियों को काम पर लगाते हैं। यह लंबी और मजबूत श्रृंखला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले का 19 वर्षीय सलीम खान इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। वह आक्रामक और सख्त लहजे में स्वीकार करता है कि वह कमसिन लड़कियों को लुभाने के लिए नकली नोट दिखाता है और उन्हें पैसे देने और शादी करने के सब्जबाग दिखाता है। हाल ही में गोरखपुर में उसे 14 वर्षीया प्रेमशीला के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे उसने अपने साथ भागने के लिए मजबूर किया। वह उसे दिल्ली में बेचने वाला था। दो पतली चुटियों वाली सांवली, छरहरी प्रेमशीला ने मर्दों के अपने कद से बड़े कपड़े पहन रखे हैं। पहले वह कहती है कि खान उसका भावी पति है, लेकिन बाद में वह रोते हुए मानती है कि दो साल से वह व्यक्ति उसे मारता पीटता रहा है और उसके साथ बलात्कार करता रहा है। यही नहीं, यह पैसा कमाने के लिए उसे दूसरे व्यक्तियों के साथ हमबिस्तर होने के लिए भी मजबूर करता रहा है।

5 से 15 साल की 20 लाख लड़कियां हर साल देह व्यापार में शामिल होती हैं और यह मानव तस्करी का सबसे नुमाया पहलू है। लेकिन मानव तस्करों को वेश्यावृत्ति नहीं माना जा सकता, इसमें दूसरी तरह की जबरन बिक्री भी है: घरेलू कामकाज, औद्योगिक और कृषि कार्यों, सर्कस के कारनामों, अंग व्यापार, फर्जी विवाह, भीख मांगने और गोद लेने के फर्जीवाड़े के लिए।

भारतीय समाज का एक वर्ग जहां अपने बच्चों को वातानुकूलित प्लेस्कूलों और किशोरों को मौज-मस्ती वाली पार्टियों में भेजता है, वहीं दूसरा वर्ग, अपनी लड़कियों को बेच देता है। बेटियों को इतनी कम अहमियत दी जाती है और भूख से उठने वाली पीड़ा इतनी असह्य होती है कि कोई भी व्यक्ति गांव जाकर किसी गरीब परिवार की शिनाख्त करके आधे घंटे से भी कम समय की बातचीत में कुछेक हजार रु. में एक लड़की खरीद सकता है। लड़कियों को खरीदना वाकई इतना ही आसान है। उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण से जब यह पूछा गया कि उसके कितने बच्चे हैं तो उसका जवाब या, "तीन बच्चे, और पांच बेटियां।,"

पंजाब के दालेरसिंहवाला गांव में इंडिया टुडे ने कई ऐसे गरीब दलित परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने अपनी बेटियां, जिनमें से कुछ 8-10 साल की हैं, स्थानीय जमींदारों को बंधुआ मजदूर के रूप में बेच दी हैं। 14 वर्षीया गुरप्रीत कौर, जिसको आंखें पीली हो गई हैं और पैर सूजे हुए हैं, को 6,000 रु में बेचा गया। सिर पर दुपट्टा डाले गुरप्रीत पौ फटते ही काम करने लग जाती है और उसे पहली बार दिन में दो बजे खाना दिया जाता है। यह तब तक इसी तरह मुसीबत झेलती रहेगी जब तक उसके मां-बाप जमींदार को पूरी रकम न चुकादें या फिर किसी दिन वह इसी तरह काम करते हुए खेत में ही गिरकर दम न तोड़ दे।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की शालू 13 साल की उम्र में ही दिल्ली की बदनाम जीबी रोड पर काम करने आ गई। वह कहती है, दलाल हमारे गांवों से लड़कियां लाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम खाना, कपड़े, साफ-सफाई और पेयजल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शालू के आठ भाई-बहन, लकवाग्रस्त पिता और असहाय मां को रोज-रोज खाना तभी नसीब हुआ जब उसने वेश्या के रूप में काम शुरू किया। अब खाने वाले लोगों की तादाद और बढ़ गई है। 15 साल की उम्र में ही उसने पहले बच्चे को जन्म दिया था और अब फिर गर्भवती हो गई है।

एक ओर गांव खरीदारी के केंद्र है, उसी तरह मुंबई, दिल्ली और कोलकाता इस कारोबार के सबसे बड़े अड्डे हैं. आयात निर्या का केंद्र मुंबई इस अपराध की निर्विवाद राजधानी है। इस धंधे से मुक्त कराई गई लड़कियों ने रांची, नेपाल और मुर्शिदाबाद में बातचीत में बार-बार मुंबई का जिक्र किया। गोवा के वास्को दा गामा में बैना जैसे पर्यटक स्थल भी मानव तस्करी के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा अब तस्करी के नक्से में ऐसे राज्य के रूप में देखे जाते हैं जहां लड़कियां बेची जा सकती हैं। पंजाब में नौकरानी और कृषि मजदूर या "पत्नी" बनने के लिए, और हरियाणा में वेश्यावृत्ति या अंग व्यापार के लिए।

लड़कियों के गांवों से शहर के सफर के साथ ही उसमें नए-नए किरदार शामिल हो जाते हैं। महिला तस्कर अक्सर बूढ़ी वेश्याएं होती हैं, जिनके सामने पुनर्वास की कोई संभावना नहीं होती। कभी खुद पीड़ित रहीं ये बूढ़ी महिलाएं उत्पीड़क बन गई हैं। वहीं, पुरुप खुलेआम जोर-जबरदस्ती करते हैं। लड़कियों की कीमत उनके बिकने योग्य गुणों पर तय की जाती है। गांवों में उनकी कीमत 2,000-4,000 रु. होती है लेकिन मुंबई के मयखाने तक पहुंचते-पहुंचते उनकी कीमत 50,000 रु. तक हो जाती है। यह कारोबार तीन स्तरों पर चलता है. गांव में खरीदारी करने वाले लड़कियों को फंसाते हैं, उन्हें ट्रेन के जरिए प्राथमिक खरीदार तक पहुंचाते हैं। ये तस्कर फिर उन लड़कियों को ठिकाने लगाते हैं। और उन्हें उनके

शारीरिक गुणों के आधार पर इस धंधे के विभिन्न हिस्सों में लगाते हैं। अंतिम बिक्री में कुछ समय लगता है पर इस बीच उनका शोषण जारी रहता है, जो उनके घर से बाहर कदम रखते ही शुरू हो जाता है। अक्सर उनके साथ सबसे पहले वही व्यक्ति बलात्कार करता है, जो उन्हें सबसे पहले खरीदता है और सबसे पहली बिक्री गांव की सीमा पर ही हो जाती है। उसके बाद से उन पर "बिकी हुई" का लेवल मानो उनके भाग्य की तरह चस्पा हो जाता है।

घरेलू कामकाज इस कारोबार का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। झारखंड की स्वयंसेवी दयामणि बरला, जिन्होंने खुद एजेंट बनकर 21 लड़कियों को मुक्त कराया है, के शोध से पता चलत है कि दिल्ली की एजेंसियों ने 20,000 आदिवासी लड़कियों को घरेलू नौकरानी की नौकरी की इच्छुक के रूप में पंजीकृत किया है। ये नाराजगी जताते हुए कहती हैं, "झारखंड पुलिस और स्थानीय नेताओं ने इन गिरोहों से साठगांठ कर रखी है।"

बरला का आरोप बेजा नहीं है जैसा कि गोरखपुर में पुलिस के क्षेत्राधिकारी ए.एस. राय कहते, "इतने बड़े पैमाने पर संगठित आपराधिक गतिविधियां पुलिस की मिलीभगत के बिना शायद ही चल सकती है।" इसके अलावा, कुछ पुलिसकर्मी मानवाधिकार का उल्लंघन करते है। शालू बताती है कि जीबी रोड पर छापे के बाद उसके और कुछ दूसरी लड़कियों के साथ पुलिस ने इतना क्रूर व्यवहार किया था।

आंध प्रदेश भारत का इकलौत राज्य है जहां मानव तस्कर विरोधी नीति है, और वह उसके लिए न्यायिक प्रावधानों पर काम कर रहा है। 1986 में संशोधित मानव तस्करी निरोधक कानून (आइटीपीए) अपने आप में ठोस कानूनी प्रावधान है। लेकिन इसमें केवल यौन शोषण की पीड़ितों का ही संज्ञान लिया जाता है। एनएचआरसी की सदस्य न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर का सुझाव है, "इसे तस्करी के दूसरे रूपों को परिभाषित करने के लिए विस्तृत किया जाना चाहिए," सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में राष्ट्रीय कार्य योजना और ऐसी समिति के गठन का आदेश दिया था जो वेश्यावृत्ति का गहन अध्ययन करके योजनाएं तैयार करे। पर फरीदाबाद स्थित गैर सरकारी संगठन 'शक्ति वाहिनी', जिसने वैश्यावृत्ति के संगठित अपराध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है, के ऋषिकांत श्रीवास्तव कहते हैं, "लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।"

मनोहर का मानना है कि जब तक भारत सरकार अपने 'कल्याण' कार्यक्रमों पुनर्परिभाषित नहीं करेगी और अपने नीति नियंताओं तथा पुलिस को संवेदनशील नहीं बनाएगी तब तक अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। उनका संवेदनशीलता का तर्क महत्वपूर्ण है। जब तक डांट-डपट के परे जाकर सलाह नहीं दी जाएगी, तब तक महिला पुलिसकर्मी ताने मारने के बजाए स्नेह नहीं दिखाएंगी, जब तक सिलाई सिखाने से परे उनके कल्याण का काम नहीं किया जाएगा तब प्रभावी पुनर्वास सपना ही रहेगा। इसी वजह से हैदराबाद स्थित प्रज्वला के लड़कियों को छोटे उपक्रमों की मालकिन बनाने के कार्यक्रम ज्यादा तर्कसंगत लगते हैं।

पुलिस, न्यायपालिका, नीति नियंता, गैर-सरकारी संगठन, सलाहकार और बुनियादी स्तर पर काम करने वाले स्वयंसेवियों की ओर से बहुपक्षीय उपायों की जरूरत है। गोरखपुर जैसे कुछ प्रभावित इलाकों में फल

विक्रेता, मोची, बस कंडक्टर सेवा को ऐसी लड़कियों का सुराग देने में मदद कर रहे हैं जो परेशानी में लग रहो थी। रांची के पास हर्रा गांव के ग्रामीणों ने आप्रवास विरोधी और तस्करी विरोधी समूह बना लिए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पूर्व देवदासियों ने मानव तस्करी विरोधी समूह बनाए है।

भारतीय महिलाओं की मुक्ति और प्रगति के बारे में बात करना अच्छा लगता है। लेकिन जब तक गरीब परिवार बच्चों का पेट भरने में सक्षम नहीं होते, जब तक लड़कियों को खरीदने, उनका शोषण करके बेचने वाले को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान नहीं होता तब तक शालू की कोख में पल रहे "धंधे के बच्चे" पैदा होते रहेंगे।"

10. Learned counsel for the applicants has submitted that a bare perusal of Sections 153 and 153-A IPC would indicate that no such offence is made out against the applicants. On a bare perusal of the complaint as well as the statements recorded under Sections 200 and 202 Cr.P.C. there is no sign of visible representation of either spoken or written words which promotes or attempts to create dis-harmony or feelings of enmity or hatred between the two groups or communities. Sections 153 and 153 A read as under :

"153. Wantonly giving provocation with intent to cause riot-if rioting be committed-if not committed. *Whoever malignantly, or wantonly, by doing anything which is illegal, gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offence of rioting to be committed, shall, if the offence of rioting be committed in consequence of such provocation, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both and if the offence of rioting be not committed, with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both*

*"[**153-A. Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony**.—(1) Whoever—*

(a) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity, hatred

or ill-will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, or

(b) commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb the public tranquility, 2[or]

3[(c) organises any exercise, movement, drill or other similar activity intending that the participants in such activity shall use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, or participates in such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, against any religious, racial, language or regional group or caste or community and such activity, for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of such religious, racial, language or regional group or caste or community,]

shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both."

11. Learned counsel for the applicants has relied upon the judgment of Hon'ble Supreme Court reported in ***(2007) 5 SCC 1 (Manzar Sayeed Khan vs. State of Maharastra).*** Relevant para nos.15, 16 and 17 are quoted hereinbelow :

"15. *We have given our thoughtful consideration to the respective contentions of the learned counsel for the parties. The question to be decided now is whether the paragraph complained of would attract the penal consequences envisaged in Section 153-A IPC. Section 153-A IPC was amended by the Criminal Law (Amendment) Act, 1969 (Act 35 of 1969). It consists of three clauses of which clauses (a) and (b) alone are material for the case on hand, which read as under:[**153-A. Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony**.—(1) Whoever—*

(a) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, place of birth,

residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, or

(b) commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb the public tranquillity, 2[or]

3[(c) organises any exercise, movement, drill or other similar activity intending that the participants in such activity shall use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, or participates in such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, against any religious, racial, language or regional group or caste or community and such activity, for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of such religious, racial, language or regional group or caste or community,]

shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

16. *Section 153-A IPC, as extracted hereinabove, covers a case where a person by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities or acts prejudicial to the maintenance of harmony or is likely to disturb the public tranquility. The gist of the offence is the intention to promote feelings of enmity or hatred between different classes of people. The intention to cause disorder or incite the people to violence is the sine qua non of the offence under Section 153-A IPC and the prosecution has to prove prima facie the existence of mens rea on the part of the accused. The intention has to be judged primarily by the language of the book and the circumstances in which the book was written and published. The matter complained of within the ambit of Section 153-A must be read as a whole. One cannot rely on strongly worded and isolated passages for proving the charge nor indeed can one take a sentence here and a sentence there and connect them by a meticulous process of inferential reasoning.*

17. *In* ***Ramesh v. Union of India [(1988) 1 SCC 668 : 1988 SCC (Cri) 266 : AIR 1988 SC 775]*** *this Court held that TV serial Tamas did not depict communal tension and violence and the provisions of Section 153-A IPC would not apply to it. It was also not prejudicial to the national integration falling under Section 153-B IPC. Approving the observations of Vivian Bose, J. in Bhagwati Charan Shukla v. Provincial Govt.[AIR 1947 Nag 1] the Court observed that*

> *"the effect of the words must be judged from the standards of reasonable, strong-minded, firm and courageous men, and not those of weak and vacillating minds, nor of those who scent danger in every hostile point of view. ... It is the standard of ordinary reasonable man or as they say in English law 'the man on the top of a Clapham omnibus'." (Ramesh case [(1988) 1 SCC 668 : 1988 SCC (Cri) 266 : AIR 1988 SC 775] , SCC p. 676, para 13)"*

12. Learned counsel has also relied upon the judgment reported in **(2024) 4 SCC 156** ***Javed Ahmad Hajam vs. State of Maharastra and another.*** Relevant paras are as follows :

> ***"5****. The only offence alleged against the appellant is the one punishable under Section 153-AIPC. Section 153-AIPC, as it exists with effect from 4-9-1969, reads thus:*
>
> *"**153-A. Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony**.—(1) Whoever—*
>
> *(a) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, or*
>
> *(b) commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb the public tranquillity,*
>
> *(c) organises any exercise, movement, drill or other similar activity intending that the participants in such activity shall use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or*

violence, or participates in such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, against any religious, racial, language or regional group or caste or community and such activity, for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of such religious, racial, language or regional group or caste or community,

shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

Offence committed in place of worship, etc.—*(2) Whoever commits an offence specified in sub-section (1) in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine."*

6. In this case, clause (c) of sub-section (1) of Section 153-AIPC is admittedly not attracted.

7. In the case of ***Manzar Sayeed Khan [Manzar Sayeed Khan v. State of Maharashtra, (2007) 5 SCC 1 : (2007) 2 SCC (Cri) 417]*** *, while interpreting Section 153-A, in para 16, this Court held thus : (SCC p. 9)*

"16. Section 153-A IPC, as extracted hereinabove, covers a case where a person by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities or acts prejudicial to the maintenance of harmony or is likely to disturb the public tranquillity. The gist of the offence is the intention to promote feelings of enmity or hatred between different classes of people. The intention to cause disorder or incite the people to violence is the sine qua non of the offence under Section 153-AIPC and the prosecution has to prove prima facie the existence of mens rea on the part of the accused. The intention has to be judged primarily by the language of the book and the circumstances in which the book was written and published. The matter complained of within the ambit of Section 153-A must be read as a whole. One cannot rely on strongly worded and isolated passages for proving the charge nor indeed can one take a sentence here and a sentence there and connect them by a meticulous process of inferential reasoning."

8. *This Court in Manzar Sayeed Khan [Manzar Sayeed Khan v. State of Maharashtra, (2007) 5 SCC 1 : (2007) 2 SCC (Cri) 417] referred to the*

view taken by Vivian Bose, J., as a Judge of the erstwhile Nagpur High Court in Bhagwati Charan Shukla v. Provincial Govt. [Bhagwati Charan Shukla v. Provincial Govt., 1946 SCC OnLine MP 5 : AIR 1947 Nag 1] A Division Bench of the High Court dealt with the offence of sedition under Section 124-AIPC and Section 4(1) of the Press (Emergency Powers) Act, 1931. The issue was whether a particular article in the press tends, directly or indirectly, to bring hatred or contempt to the Government established in law. This Court has approved this view in its decision in Ramesh v. Union of India [Ramesh v. Union of India, (1988) 1 SCC 668 : 1988 SCC (Cri) 266] . In the said case, this Court dealt with the issue of applicability of Section 153-AIPC. In para 13, it was held thus : (Ramesh case [Ramesh v. Union of India, (1988) 1 SCC 668 : 1988 SCC (Cri) 266] , SCC p. 676)

"13. …the effect of the words must be judged from the standards of reasonable, strong-minded, firm and courageous men, and not those of weak and vacillating minds, nor of those who scent danger in every hostile point of view. … It is the standard of ordinary reasonable man or as they say in English law 'the man on the top of a Clapham omnibus'. (Bhagwati Charan Shukla case [Bhagwati Charan Shukla v. Provincial Govt., 1946 SCC OnLine MP 5 : AIR 1947 Nag 1] , SCC OnLine MP para 67)"

Therefore, the yardstick laid down by Vivian Bose, J., will have to be applied while judging the effect of the words, spoken or written, in the context of Section 153-AIPC.

9. *We may also make a useful reference to a decision of this Court in Patricia Mukhim v. State of Meghalaya [Patricia Mukhim v. State of Meghalaya, (2021) 15 SCC 35] . Paras 8 to 10 of the said decision read thus : (SCC pp. 41-43)*

"8. 'It is of utmost importance to keep all speech free in order for the truth to emerge and have a civil society.'— Thomas Jefferson. Freedom of speech and expression guaranteed by Article 19(1)(a) of the Constitution is a very valuable fundamental right. However, the right is not absolute. Reasonable restrictions can be placed on the right of free speech and expression in the interest of sovereignty and integrity of India, security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or in relation to contempt of Court, defamation or incitement to an offence. Speech crime is punishable under Section 153-AIPC. Promotion of enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony is punishable with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both under Section 153-A. As we are called upon to decide whether a prima facie case is made out against the appellant for committing offences under Sections 153-A and 505(1)(c), it is relevant to reproduce the provisions which are as follows:

***

9. Only where the written or spoken words have the tendency of creating public disorder or disturbance of law and order or affecting public tranquillity, the law needs to step in to prevent such an activity. The intention to cause disorder or incite people to violence is the sine qua non of the offence under Section 153-AIPC and the prosecution has to prove the existence of mens rea in order to succeed. [Balwant Singh v. State of Punjab, (1995) 3 SCC 214 : 1995 SCC (Cri) 432]

10. The gist of the offence under Section 153-AIPC is the intention to promote feelings of enmity or hatred between different classes of people. The intention has to be judged primarily by the language of the piece of writing and the circumstances in which it was written and published. The matter complained of within the ambit of Section 153-A must be read as a whole. One cannot rely on strongly worded and isolated passages for proving the charge nor indeed can one take a sentence here and a sentence there and connect them by a meticulous process of inferential reasoning [Manzar Sayeed Khan v. State of Maharashtra, (2007) 5 SCC 1 : (2007) 2 SCC (Cri) 417] ."

(emphasis in original and supplied)

***10.** Now, coming back to Section 153-A, clause (a) of sub-section (1) of Section 153-AIPC is attracted when by words, either spoken or written or by signs or by visible representations or otherwise, an attempt is made to promote disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities. The promotion of disharmony, enmity, hatred or ill will must be on the grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste, community or any other analogous grounds. Clause (b) of sub-section (1) of Section 153-AIPC will apply only when an act is committed which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities and which disturbs or is likely to disturb the public tranquillity.*

***11.** Now, coming to the words used by the appellant on his WhatsApp status, we may note here that the first statement is that August 5 is a Black Day for Jammu and Kashmir. 5-8-2019 is the day on which Article 370 of the Constitution of India was abrogated, and two separate Union Territories of Jammu and Kashmir were formed. Further, the appellant has posted that "Article 370 was abrogated, we are not happy". On a plain reading, the appellant intended to criticise the action of the abrogation of Article 370 of the Constitution of India. He has expressed unhappiness over the said act of abrogation. The aforesaid words do not refer to any religion, race, place of birth, residence, language, caste or community. It is a simple protest by the appellant against the decision to abrogate Article 370 of the Constitution of India and the further steps taken based on that decision. The Constitution of India, under Article 19(1)(a), guarantees freedom of speech and expression. Under the said guarantee, every citizen has the*

right to offer criticism of the action of abrogation of Article 370 or, for that matter, every decision of the State. He has the right to say he is unhappy with any decision of the State.

12. *In* ***Manzar Sayeed Khan [Manzar Sayeed Khan v. State of Maharashtra, (2007) 5 SCC 1 : (2007) 2 SCC (Cri) 417]*** *, this Court has read "intention" as an essential ingredient of the said offence. The alleged objectionable words or expressions used by the appellant, on its plain reading, cannot promote disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities. The WhatsApp status of the appellant has a photograph of two barbed wires, below which it is mentioned that "AUGUST 5 — BLACK DAY — JAMMU & KASHMIR". This is an expression of his individual view and his reaction to the abrogation of Article 370 of the Constitution of India. It does not reflect any intention to do something which is prohibited under Section 153-A. At best, it is a protest, which is a part of his freedom of speech and expression guaranteed by Article 19(1)(a).*

13. *Every citizen of India has a right to be critical of the action of abrogation of Article 370 and the change of status of Jammu and Kashmir. Describing the day the abrogation happened as a "Black Day" is an expression of protest and anguish. If every criticism or protest of the actions of the State is to be held as an offence under Section 153-A, democracy, which is an essential feature of the Constitution of India, will not survive.*

14. *The right to dissent in a legitimate and lawful manner is an integral part of the rights guaranteed under Article 19(1)(a). Every individual must respect the right of others to dissent. An opportunity to peacefully protest against the decisions of the Government is an essential part of democracy. The right to dissent in a lawful manner must be treated as a part of the right to lead a dignified and meaningful life guaranteed by Article 21. But the protest or dissent must be within four corners of the modes permissible in a democratic set up. It is subject to reasonable restrictions imposed in accordance with clause (2) of Article 19. In the present case, the appellant has not at all crossed the line.*

(emphasis supplied)

13. Learned counsel for the applicant has also placed reliance upon **(2024) 7 SCC 555 ;** ***2024 SCC OnLine SC 322 (Shiv Prasad Semwal vs. State of Uttarakhand and others*** to support his case.

14. Learned AGA has opposed the submissions and has submitted that the article which was published makes out offence,

therefore, the summoning order passed by the trial court is correct in the eye of law.

15. After going through the record as well as the submissions of the rival parties hereinabove, this Court finds that there is no such situation where court may come to the conclusion that the applicants by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious, racial language or regional groups or castes or communities or acts prejudicial to the maintenance of harmony or is likely to disturb the public tranquility. The source of article is also mentioned and the information has been brought in the magazine to the extent that minor girls are used for sexual abuse (Annexure 2), which is a part of the Magazine. The basis and source of information is mentioned wherein it is evident that Murshidabad District of West Bengal has become a hub of human trafficking where the minor girls are sold for sexual gratification. Even if it is mentioned that there is unrest in Bediya community, it does not mean that it is a case of disharmony between the two groups or community. It is nowhere mentioned that Bediya community has unrest against muslim community. The intention has to be judged by the language of the article published in 'Indian Today' Magazine.

16. Article 19 (1) (a) enshrined under Chapter III of the Constitution of India essentially a fundamental right guarantees that a citizen has a right to freedom of speech and expression and in the present case, facts of a particular area pertaining to the minor girls and their sexual exploitation has been published ; certainly the plight of sexual exploitation of minor girls depicted

in the magazine does not create any disharmony or unrest between two groups or communities. The sex slavery of the minor girls have been highlighted and there is no intention of the applicants to promote any kind of hatred between the two communities.

17. In view of the facts and circumstances, of the case, the summoning order dated 07.05.2007 issued under Sections 153/153A IPC., is set aside as well as the entire criminal proceedings pending in the court of Special Judicial Magistrate, (CBI), Lucknow vide RBT No.C-186 of 2006 bearing Complaint Case No.626 of 2004, (Ehtisham Mirza vs. Arun Purie and others), Police Station Chowk, District Lucknow is quashed.

18. The application under Section 482 Cr.P.C. is allowed.

(BRIJ RAJ SINGH, J.)

October 13, 2025
Pks

Digitally signed by :-
POOJA SETH
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench